# भारतीय जनता पार्टी
## राष्ट्रीय परिषद् की बैठक
## श्री सुंदर सिंह भण्डारी परिसर
### लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)
**दिसंबर 23–24, 2006**

## प्रस्ताव
## आम आदमी के साथ विश्वासघात

भाजपा की राष्ट्रीय परिषद बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री वेंकैया नायडू ने 'संप्रग शासन में आम आदमी के साथ विश्वासघात' विषय पर प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का अनुमोदन प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी ने किया। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्तुत है प्रस्ताव का पूरा पाठः–

संप्रग सरकार के ढाई साल पूरे हो गए हैं। इसका आधा शासनकाल बीत चुका है। यदि इसके प्रदर्शन पर सरसरी नजर डालें तो पता चलता है कि सरकार ने देश के आम आदमी की जीविका व उनके जीवन पर कुठाराघात किया है।

भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस–नीत सरकार की जन–विरोधी नीतियां, मई 2004 में सरकार में आने के सिर्फ एक साल अंदर ही उजागर हो गईं। अनपेक्षित ढंग से सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस पार्टी ने शुरू में ही संकेत दे दिया कि चुनाव पूर्व किए गए वायदे, कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ, के प्रति न तो यह संवेदनशील है और न ही उसके प्रति पूर्णरूपेण समर्पित। कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना रिकार्ड है कि जब भी वह सत्ता में आई तो उसने चुनावी घोषणापत्र में दिए गए वायदों से मुकर गई– 1971 में गरीबी हटाओ, 1980 में उस सरकार को वोट जो काम करे या 1984 उस सरकार को वोट जो तेजी से काम करती है। लेकिन इस समय केंद्र में एक ऐसा गठबंधन है, जिसके बारे में कहा जा सकता हैः यह वह सरकार है, जो वायदों से मुकरने में सबसे आगे है।

संप्रग सरकार के शासनकाल का हर बीता हुआ महीना भाजपा द्वारा लगाए गए दो आरोपों की पुष्टि करता है। आरोप एक; 'कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ' की जगह कांग्रेस का हाथ, आम आदमी से विश्वासघात के रूप में बदल गया है। आरोप दो; कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ न होकर 'कांग्रेस का हाथ, खास आदमी के साथ' में परिवर्तित हो गया है।

पहला आरोप सिद्ध होने की खास वजह आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अभूतपूर्व व निरंतर वृद्धि है, जिसने आम आदमी की सीमित आय को खोखला कर उनपर अनगिनत कठिनाइयां लाद दीं। दूसरा आरोप इस बात से सिद्ध होता है कि भारतीय समाज में अल्पसंख्यक अमीरों के पास असीमित धन व बहुसंख्यक गरीबों के बीच की खाईं बढ़ी है। हालांकि, संप्रग सरकार मुंबई स्टाक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक को 13,500 को पार करने को प्रदर्शित करती है, वहीं किसानों के आत्महत्या सूचकांक की लगातार वृद्धि पर आंखे बंद कर ली है। अजीब विडंबना है कि संप्रग सरकार के अंदर इंडिया तो चमकती जा रही है, लेकिन आम आदमी की चमक धुंधली से धुंधली होती जा रही है।

**मूल्य नियंत्रण पर विफलताः**

सितंबर के शुरू में देहरादून में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भाजपा ने सावधान किया था कि संप्रग सरकार आम आदमी की कठिनाइयों से आंखें फेर ली है, क्योंकि सरकार आवश्यक वस्तुओं के आसमान छूती कीमतों पर नियंत्रण पाने में विफल रही है। राष्ट्रीय परिषद् इस मुद्दे को पुनः उठाने के लिए मजबूर है, क्योंकि इस मामले में सरकार लगातार अक्षम रही है व अनिच्छा प्रदर्शित कर रही है। जैसा कि संलग्न चार्ट प्रदर्शित करता है कि हर खाद्य पदार्थों के मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई है, न केवल मई 2004 से जब राजग सरकार ने सत्ता छोड़ी थी, बल्कि मई 2006 से भी। दाल, जो आम भारतीय के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, गरीब परिवारों के नियमित आहार से लगभग गायब हो गई थी। समाज के सबसे गरीब तबकों में आज प्रति व्यक्ति खाद्य उपभोग 20 साल पहले से कम है।

पिछले तीन महीनों में एक खास बात यह हुई है कि तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य काफी कम हुए हैं। इसकी कीमत 71 डालर प्रति बैरल से घटकर आज 51 डालर प्रति बैरल हो गई है। सामान्यतया जब पेट्रोल व डीजल की कीमत बढ़ती है, तो उनका दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था में सभी दूसरी वस्तुओं और सेवाओं पर पड़ता है। लेकिन असामान्य बात यह है कि आयातित तेल के मूल्य में कमी आने के बावजूद संप्रग सरकार के अंदर आम आदमी के दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के दाम कम नहीं हुए।

राजग सरकार के 6 साल के शासनकाल में मुद्रास्फीति की औसत दर 3.4 फीसदी थी। संप्रग सरकार के 30 महीने के कार्यकाल में यह 5 फीसदी या इससे ऊपर रही है। मई 2004 से लगातार मूल्यवृद्धि ने इस सहज अनुमान को सिद्ध कर दिया है कि जब भी कांग्रेस केंद्र में सत्ता संभालती है, मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार, वस्तुओं की अनुपलब्धता, प्रतीक्षा की लंबी सूची और लंबी–लंबी कतारें तथा काला–बाजारी  साथ साथ आती है।

भाजपा के दबाव के कारण संप्रग सरकार ने पेट्रोल व डीजल की कीमत में मामूली कमी की घोषणा की, लेकिन यह अंतराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में आई गिरावट के अनुरूप नहीं थी। सच तो यह है कि इस घोषणा की असर मूल्य वृद्धि पर नहीं पड़ा। यही कारण है कि सीपीआई और सीपीआई(एम), जो यूपीए के सहयोगी दल है, ने सरकार की घोषणा पर नाराजगी जाहिर की और कहा, बहुत कम वह भी काफी देर से। दरअसल, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी ए.बी. बर्द्धन यह कहने पर मजबूर हो गए कि संप्रग सरकार ने पूरी स्थिति को गड्डमगड्ड कर दिया है।

**साम्यवादी पाखंड**

हालांकि, भाजपा का राष्ट्रीय परिषद् कांग्रेस पार्टी द्वारा आम आदमी के प्रति की गई धोखाधड़ी को उजागर करती है, लेकिन यह जरूरी है कि यूपीए सरकार के साम्यवादी सहयोगियों के पाखंड व छलकपट को भी प्रकट किया जाय। 14 दिसंबर को वामपंथी पार्टियों ने सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया था, जिसे उनके ट्रेड संगठनों का समर्थन प्राप्त था। हालांकि केरल और पश्चिम बंगाल के बाहर बंद का असर बहुत कम था, लेकिन इसने साम्यवादियों की दोमुंही नीति को स्पष्ट कर दिया कि बाहर अपने समर्थकों को खुश करने के लिए विरोध का लाल झंडा और केंद्र में बिना उत्तरदायित्व के सत्ता सुख के लिए हरा झंडा।

**किसानों को दिए गए वायदों के साथ धोखाधड़ी**

भाजपा की राष्ट्रीय परिषद् बड़ी व्यथा के साथ कहती है कि भारतीय कृषि की बहु आयामी जरूरतों को पूरा करने में संप्रग सरकार लगातार विफल रही है, जिससे देश के अधिकांश भागों के किसान दुर्दशा के शिकार हो गए, उनकी हालत बदतर होती गई, उन पर कर्ज बढ़ते गए तथा आयात पर निर्भरता बढ़ी। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान लगातार गिर रहा है, हालांकि इस पर निर्भर रहने वालों की तादाद् पहले से ही बहुत ज्यादा है। परिणामस्वरूप कृषि द्वारा अर्जित आय व रोजगार में लगातार गिरावट दर्ज की गई। यह ट्रेंड चेतावनी सूचक है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अनर्थकारी व ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना को नष्ट करने वाला है, लेकिन संप्रग सरकार इस वास्तविकता से अत्यंत उदासीन है। बड़ी संख्या में किसानों द्वारा हताशा में की गई आत्महत्या, खासतौर पर कांग्रेस शासित राज्यों–महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल व पंजाब, गहराते कृषि संकट का परिचायक है। संप्रग सरकार ने, जिसने समस्या को हल करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने का वायदा किया था, अपने वादे को पूरा करने में राजनीतिक अनिच्छा और अक्षमता का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री का बहुप्रचारित ऋण सहायता पैकेज केवल देश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। इसलिए यह राष्ट्रीय के बजाय सांकेतिक पैकेज है। यह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए भी असफल रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा के बावजूद वहां ऋणग्रस्त किसानों की आत्महत्या का सिलसिला बिना कम हुए लगातार जारी रहा। सच तो यह है कि आत्महत्या की दर और बढ़ गई। यह इसलिए हुआ कि संप्रग सरकार ने समस्या की जड़ का प्राथमिकता के आधार पर हल नहीं किया। कृषि उत्पादन में कमी, सिचाईं सुविधाओं का अभाव, लागत में बढ़ोत्तरी व उत्पादों के मूल्यों में कमी, विज्ञान व तकनीकी साधनों का कम प्रयोग, छोटे व मझोले किसानों को क्रेडिट मुहैया कराने वाली संस्थाओं की लगभग अनुपस्थिति, कृषि उत्पाद के लिए अपर्याप्त मार्केटिंग सुविधाएं, फसल बीमा का यत्र–तत्र प्रयोग व अप्रभावी लागू होना और ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास में लापरवाही, इसका सबसे अच्छा उदाहरण वाजपेई सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की यूपीए सरकार द्वारा अनदेखी। राजग सरकार

का इरादा 2007 तक हर गांव को  जिसकी आबादी 1000 या इससे अधिक है बारहमासी सड़क से जोड़ने का था। यह लक्ष्य कही भी पूरा होते दिखाई नहीं पड़ता।

## घरेलू खाद्य सुरक्षा का परित्याग

डा.एम. एस. स्वामीनाथम की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आयोग (किसानों पर) की एक बड़ी सिफारिश यह थी कि भारत को एक ऐसी घरेलू खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए, जो देश के हर नागरिक को पर्याप्त, पहुंच के अंदर, पौष्टिक व संतुलित खाद्य पदार्थ मुहैया करा सके। आयोग ने कहा कि यह लक्ष्य देश के किसानों द्वारा उत्पादन बढ़ाकर, कृषि उत्पाद में बढ़ोत्तरी करके व कृषि उत्पादों के उचित मूल्य देकर हासिल किया जा सकता है। आयोग ने सुझाव दिया कि जहां तक संभव हो किसानों को प्राप्त होने वाले मूल्य और शहरी उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए मूल्य के बीच का अंतर कम होना चाहिए। आयोग ने इस तथ्य पर चिंता जाहिर की मुख्य खाद्य फसलों की पैदावार व फसल–क्षेत्र घट रहे हैं। वास्तव में पैदावार में बढ़ोत्तरी की दर 1980 में 3.75 फीसदी से गिरकर इस समय 1 फीसदी रह गई है।

आयोग ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि आयात पर निर्भरता भारतीय किसानों के हितों के विरूद्ध होगी। और जैसा कि अभी हाल में किए गए गेहूं आयात से पता चलता है कि ये आयात बिना सोचे समझे किए गए, गलत समय पर हुए और देश के गेहूं–उत्पादकों पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ा। प्रतिवर्ष गेहूं की खरीदारी भी जानबूझ कर घटाई जा रही है। 2002 में 206 लाख मीटरिक टन से घट कर अब यह 2006 में मात्र 92 लाख मीटरिक टन रह गई है। साथ ही साथ, यूपीए सरकार राज्यों को गेहूं का आवंटन घटाना चाहती है। समग्र ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) में खाद्यान्न आवंटन की मात्रा घटा रही है, गरीबी रेखा से ऊपर के (एपीएल) परिवारों के खाद्यान्नों की कीमतें सरकार बढ़ाती जा रही है और इन परिवारों के मासिक कोटे को भी घटा रही है (इनमें से बहुत से परिवार तो वास्तव में गरीबी रेखा के कगार पर है)।

भाजपा की राष्ट्रीय परिषद आगाह करना चाहती है कि यूपीए सरकार की सोच और उसके कार्य स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के विपरीत हैं। किसानों और उपभोक्ताओं दोनों ही दृष्टियों से आज भारत खाद्यान्न के मोर्चे पर जितना असुरक्षित महसूस कर रहा है, उतना पहले उसने कभी नहीं किया।

## ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की 'हत्या'

यूपीए के न्यूनतम साझा कार्यक्रम मे सबसे बड़ा वायदा यह किया गया था कि यह सरकार 'जल्द ही' देशभर में एक कार्यक्रम शुरू कर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारण्टी देगी। सरकार की 'जल्दी ही' की परिभाषा यह रही कि उसने कार्यक्रम तैयार करने में ही 18 महीने लगा दिए। इसके बाद उसने छह महीने और धन का आवंटन करने में लगा दिए, फिर जो राशि आवंटित की गयी वह न केवल योजना के लिए अल्पराशि है, बल्कि अधिकांशतः इस राशि को पिछली ग्रामीण विकास योजनाओं से परिवर्तित कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी (एनआरईजीसी) योजना भी राष्ट्रव्यापी नहीं है, क्योंकि इसे केवल 200 जिलों तक ही सीमित रखा गया है। विख्यात अर्थशास्त्री प्रो. जीन ड्रेज इस योजना की अवधारणा से जुड़े रहे हैं; उनका इस बारे में यह कहना हैः ''इस योजना के बारे में बड़ा हो –हल्ला किया गया, परन्तु जहां तक कारगर कार्रवाई करने की बात रही, वहां अपेक्षतया कुछ नहीं हुआ..... राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सरकार के लिए बड़ा सुनहरा अवसर था कि वह आम आदमी के लिए अपना वायदा निभा सकती थी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने उसे यह अवसर भी मुहैया कराया था परंतु  सरकार ने संसद में रखने से पहले ही इसका गला घोंट दिया गया।''

हाल में निष्पक्ष सर्वेक्षणों से पता चलता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सबसे अधिक कार्यान्वयन गैर–कांग्रेसी राज्यों, विशेष रूप से भाजपा–शासित राज्यों में हो रहा है। वास्तव में जहां तक इस (एनआरईजीपी) का प्रश्न है, सबसे बदतर कार्यान्वयन दो राज्यों में हुआ है और वे है– कम्युनिस्ट शासित पश्चिम बंगाल तथा कांग्रेस शासित महाराष्ट्र। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरी करने के प्रसंग में राष्ट्रीय परिषद ने अभी हाल में ज्योति ग्राम योजना शुरू करने पर गुजरात सरकार को बधाई दी है, जिसके अन्तर्गत राज्य के 18,000 गांवों और उप–ग्रामों को निर्बाध रूप से पूरे सप्ताह चौबीसों घंटे बिजली मिलती रहती है।

यूपीए सरकार कर्मचारी–विरोधी, मध्यमवर्गीय–विरोधी और वरिष्ठ नागरिक–विरोधी सरकार हैः भाजपा की राष्ट्रीय परिषद एक और समस्या को सामने रखता चाहती है, जिसके कारण संगठित सेक्टरों के कर्मचारियों और मध्यमवर्गीय परिवारों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। एनडीए शासन के दौरान अर्थव्यवस्था

के अच्छे प्रबंधन की कृपा से भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए बैंक ऋणों की ब्याज दरें बहुत अधिक नीचे रखी गई थीं। इसके कारण देश में मकान बनाने की झडी लग गई थी। यूपीए शासन के अन्तर्गत भवन–निर्माण और अन्य ऋणों की ब्याज दरें फिर से बढ़ने लगी हैं, हालांकि विभिन्न प्रकार की जमा राशि योजनाओं की दरें कमोवेश स्थिर बनी हुई हैं। इससे पहले यूपीए ने ईपीएफ की ब्याज दरों में 9.5 प्रतिशत से घटा कर 8.5 प्रतिशत करके अपनी मजदूर–विरोधी प्रवृत्ति को दर्शा दिया है। इससे विशेष रूप से सेवानिवृत्त लोग और वरिष्ठ नागरिकों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें बहुत से लोग तो ब्याज की आय पर बुरी तरह से निर्भर रहते हैं।

**हमारी मांगें:**

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की मांग हैः

1. अ) यूपीए सरकार को अपनी कुम्भकर्णी नींद से उठना चाहिए और आम आदमी, किसानों, असंगठित तथा संगठित सेक्टरों के मजदूरों/कर्मचारियों, मध्यमवर्गीय तथा वरिष्ठ नागरिकों के कष्टों को दूर करने के लिए तुरन्त कारगर उपाए करने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे लोगों का आक्रोश सहना पड़ेगा तथा निःसंदेह ही उसके सामने सत्ता में रहने का खतरा पैदा हो जाएगा।

   ब) सरकार को तुरन्त राजग सरकार द्वारा प्रस्तावित कृषि आय बीमा योजना को लागू करना चाहिए।
2. सरकार को ऐसे सभी क्षेत्रों में सभी किसानों की ब्याज राशि को तुरन्त माफ करने की घोषणा करनी चाहिए, जहां बार–बार फसलें (विशेष रूप से बारिश वाली फसलों के क्षेत्रों में) बर्बाद हो जाती है, जहां किसानों को भारी कर्ज के नीचे दबे रहना पड़ता है और जहां किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं।
3. सरकार को तुरन्त ही राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों पर विचारविमर्श करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाना चाहिए और सहमत एजेण्डे को चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित करने के लिए खाका तैयार करना चाहिए।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनियोजित करना होगा और कारगर ढंग से समाजिक लेखापरीक्षा तथा नियंत्रण द्वारा भ्रष्टाचार के कैंसर से मुक्त कराना होगा। एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई अन्त्योदय अन्न योजना के आधार पर आवश्यक खाद्यान्नों तथा गैर–खाद्यान्नों की सूची बना कर कम कीमतों पर सभी बीपीएल परिवारों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एपीएल परिवारों को खाद्यान्न आवंटन को भी फिर से बहाल करना होगा।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को निम्नलिखित विशेषताओं को रखते हुए पुनः तैयार किया जाना चाहिए:

   (क) कार्यक्रम के शुरू में 20,000 करोड़ प्रतिवर्ष की धनराशि का आवंटन बढ़ाया जाए और फिर प्रतिवर्ष आवश्यकता के अनुसार इसमें बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए।

   (ख) न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वायदे के अनुसार कवरेज एरिया को 200 जिलों से बढ़ा कर सभी जिलों में कर दिया जाए।

   (ग) क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक 'मांग–संचालित' कार्यक्रम है, इसलिए तुरन्त ही इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं ताकि सभी जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें।

   (घ) एनआरईजीपी के अन्तर्गत निर्माण कार्यों को स्थायी लाभकारी सम्पदा और गांवों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ जोड़ना चाहिए, जैसाकि क्रमिक पंचायती राज संस्थानों ने निर्णय किया था।

   (ड़) इमदादी कर्मचारियों की नियुक्ति और शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए जाने चाहिए।
6. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और अन्य जमाराशि योजनाओं की ब्याज दरों में तुरन्त वृद्धि की जानी चाहिए।
7. अ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज़) की स्थापना के लिए भूमि के बारे में सरकार को उन मांगों तथा विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए, जिनके बारे में हाल में ही भाजपा के दस्तावेज में इन्हें दिया गया है। विशेष रूप से सरकार को सेज़ तथा अन्य ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए उर्वरा कृषि भूमि को अधिग्रहण तथा आवंटन नहीं करना चाहिए।

ब) जब कभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आवंटित भूमि, जिसे समाज का कमजोर वर्ग जोत रहा है, उसका अधिग्रहण किया जाये तो भूमि का मुआवजा बाजार दर पर दिया जाना चाहिए।

स) जिस तरह नियमों और कानून को दरकिनार करते हुए बड़ी संख्या में (विशेष आर्थिक क्षेत्र) बनाने के प्रस्तावों को बड़ी संख्या में मंजूरी दी गई है भाजपा इसकी जांच की मांग करती है।

8. भाजपा सरकार से यह मांग करती है कि वह असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना प्रस्तुत करे।

भाजपा की राष्ट्रीय परिषद अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और अन्य सभी लोगों का आह्वान करती है कि वे यूपीए सरकार की आम–आदमी विरोधी, किसान–विरोधी तथा श्रमिक वर्ग–विरोधी नीतियों का डट कर विरोध करें। राष्ट्रीय परिषद सरकार को यह भी नोटिस दे देना चाहती है कि वह राष्ट्रीय जनान्दोलन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे।

## यूपीए सरकार के समय में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई बेतहाशा मूल्य वृद्धि की एक झलक दिखलाती तालिका

| वस्तुएं | मूल्य (रू.प्रति किलोग्राम.) एनडीए (मई, 2004) | मूल्य (रू.प्रति किलोग्राम.) यूपीए (दिस. 2006) |
|---|---|---|
| गेहूँ | 9 | 16–22 |
| आटा | 10 | 16–18 |
| चावल | 10 | 25–32 |
| रोटी | 8 प्रति पैकेट | 15 प्रति पैकेट |
| शक्कर | 14 | 22 |
| चाय | 80 | 150–200 |
| मूंग की दाल | 24 | 50 |
| अरहर की दाल | 26 | 38 |
| मसूर की दाल | 22 | 35 |
| चने की दाल | 25 | 42 |
| राजमा | 28 | 56 |
| बेसन | 20 | 50 |
| दूध | 14 प्रति लीटर | 21 प्रति लीटर |
| एलपीजी गैस | 244 | 295 |
| पेट्रोल | 33.15 | 47 |
| डीजल | 22.50 | 33 |
| सीमेंट | 125 प्रति बोरी | 193–210 प्रति बोरी |
| स्टील | 23000 प्रति टन | 28000 प्रति टन |
| ईटें | रू01800 / 1000 प्रति हजार | 3000 / 1000 प्रति हजार |